

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012—आश्विन 6, शक 1934

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,  
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,  
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश  
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की  
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,  
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रबर समिति के प्रतिवेदन,  
(3) संसद् में पुरस्थापित विधेयक,  
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,  
(3) संसद् के अधिनियम,  
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. ई-5-845-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री के. सी. जैन, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 22 दिसम्बर 2012 तक, चौंतीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2012

क्र. ई-5-739-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री हीरालाल त्रिवेदी, आयएएस, प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा नियंत्रक, शासन मुद्रण एवं लेखन सामग्री, भोपाल को इस विभाग के समसंब्धक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 द्वारा दिनांक 21 से 25 अगस्त 2012 तक, पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें, दिनांक 21 से 22 अगस्त 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंब्धक आदेश दिनांक 7 अगस्त 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. परशुराम, मुख्य सचिव।

## राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्र. एफ 1-5-1992-सात-9 (नजूल).—नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (क्रमांक 33 सन् 1976) की धारा-2 के खण्ड (डी) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन नीचे दी गई सूची के कालम (2) में वर्णित अधिकारी को उक्त सूची से कालम (3) की प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट नगर बस्ती समूह के लिये नगर भूमि सीमा (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 व 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनु.क्र.	अधिकारी का नाम	नगर बस्ती समूह
(1)	(2)	(3)
1	श्री आलोक कुमार सिंह,	इन्दौर अपर कलेक्टर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. के. रजक, अवर सचिव.

**स्कूल शिक्षा विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्र. एफ-74-4-99-बीस-2.—राज्य शासन, एतद्वारा केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल, प्रबन्ध मण्डल की नियमावली 3 (ए) में दिये गये प्रावधानों के तहत इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-74-4-99-बीस-2, दिनांक 17 जुलाई 2009 को निरस्त करते हुए केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल के प्रबंध मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को नामांकित करता है:—

### 1. सदस्य

- 3ए 1. श्री सत्यार्थ प्रकाश अग्रवाल, महामंत्री भाजपा, निवासी 2/13, सौरभ कालोनी, चांदबड़, भोपाल, म. प्र.
2. श्री महेश मकवाना, पार्षद, नगर निगम भोपाल, निवासी रेजीमेन्ट रोड, शाहजहानाबाद, भोपाल, म. प्र.
3. श्री नंदकिशोर राठौर, भाजपा कार्यालय प्रभारी, भोपाल, 87 पटेल नगर, भारत टाकिज के पास, भोपाल, म. प्र.
4. श्री गोपाल तिवारी, भाजपा मण्डल, अध्यक्ष, बस स्टेप्ट भोपाल, राजदेव कालोनी, बैरसिया रोड, भोपाल, म. प्र.

### 2. शासकीय सदस्य

3बी 5. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

3सी 6. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल.

3डी 7. प्राचार्य केम्ब्रिज स्कूल, भोपाल, मध्यप्रदेश

### 3. दानदाता सदस्य

3ठ 8. श्री अनिल अजमेरा, सामाजिक कार्यकर्ता, एस-2, रामेश्वर अपार्टमेन्ट, लालधाटी, भोपाल.

9. श्री ललित तांतेड़, सामाजिक कार्यकर्ता, आशापुरा दरबार, कोहेफिजा, भोपाल.

### 4. विधायकगण

3एफ 10. श्री उमाशंकर गुप्ता, मा. मंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, ई-22, 45 बंगले, भोपाल, म. प्र.

11. श्री ब्रह्मानन्द रत्नाकर, मा. विधायक, एमएलए, रेस्ट हाउस, भोपाल, मध्यप्रदेश,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शोभा इवनाती, उपसचिव.

### विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2012

फा. क्र. 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)-2655-12.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)

“6. श्री एन.पी.सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-3 के विशेष न्यायाधीश, (विद्युत अधिनियम), ग्वालियर एवं पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, ग्वालियर.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17(E)-8-2012-XXI-B(One)-2655-12.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Niyam, 2012, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this Department's Notifification F. No. 17(E)-8-2012-XXI-B(One), dated 02nd March, 2012, namely:—

### AMENDMENT

In the said notification, in the Table, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

### TABLE

S. No.	Name of Authorised Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
“6.	Shri N. P. Singh, Ist Additional Sessions Judge, Special Judge of Speeial Court No. 3 (Electricity Act), Gwalior and Presiding Judge, Special Court No. 2 Gwalior.	Gwalior	Area comprising of revenue district, Gwalior, Shivpuri Guna and Ashokngar.”.

This Notification shall come into force with immediate effect.

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-2656-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा

153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83/03/इक्कीस-ब (1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26, 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

### सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“26.	देवास	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	श्री राजेश कुमार गुप्ता, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.
26-ए	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.	श्री अनिल कुमार भाटिया, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.
27	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.	श्री आर. आर. भारतीय, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.	श्री कौशिक चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश कन्नौद.”.

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B-(one)-3056-11-2656-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (1), Dated 16th September, 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

### AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto, the following

serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	Dewas	IVth Additional Sessions Judge, Dewas	Shri Rajesh Kumar Gupta, IVth Additional Sessions Judge, Dewas.
26-A.	Dewas	Additional Sessions Judge, Bagli.	Shri Anil Kumar Bhatia, Additional Sessions Judge, Bagli.
27.	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch.	Shri R. R. Bhartia, Additional Sessions Judge, Sonkatch.
28.	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod.	Shri Kaushik Chouhan, Additional Sessions Judge, Kannod.”.

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब (एक)-011-2656-12.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17 (ई) 83/03/इक्कीस-ब (1), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 26, 27 एवं 28 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	देवास	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 26-ए, 27 एवं 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)

(1)	(2)	(3)	(4)
26-ए	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली.	बागली का विद्युत् क्षेत्र.
27	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ.	सोनकच्छ का विद्युत् क्षेत्र.
28	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद.	कन्नौद एवं खातेगांव का विद्युत् क्षेत्र.”.

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे।

F. No. 17(E) 83-03-3056-XXI-B-(one)-011-2656-12.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this Depratment's Notification F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (1), Dated 16th September, 2010 which was published in Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification, in the table, for serial number 26, 27 & 28 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of Territorial jurisdiction of Special Court (according to the electricity Area).
(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	Dewas	IVth Additional Sessions Judge, Dewas	All electricity Areas of Civil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction given at serial No. 26-A, 27 & 28).
26-A.	Dewas	Additional Sessions Judge, Bagli.	Electricity Area of Bagli.

(1)	(2)	(3)	(4)	
27.	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch.	Electricity Area of Sonkatch.	विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012, 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 में निमानुसार संशोधन करता हैः—
28.	Dewas	Additional Sessions' Judge, Kannod.	Electricity Area of Kannod & Khategaon.”.	संशोधन

**Note:**—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial jurisdiction.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2012

का. क्र. 1 अ-3-03-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस

आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012 एवं 14 अगस्त 2012 में श्री योगेश दांडे, विधि अधिकारी, महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर के नाम के सम्मुख अंकित “शासकीय अधिवक्ता” के स्थान पर “उप शासकीय अधिवक्ता” पढ़ा जावें।

आदेश दिनांक 13 जुलाई 2012, 14 अगस्त 2012 एवं 11 सितम्बर 2012 अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में पदस्थ विधि अधिकारी, श्री प्रवीण निवासकर के नाम के सम्मुख अंकित “शासकीय अधिवक्ता” के स्थान पर “उप शासकीय अधिवक्ता” पढ़ा जावें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे  
सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर  
आदेश

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. एफ-1-2-12-रा.स.-यू.ए. 1-1518.—राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2009 (क्र. 4 सन् 2009) की धारा 15 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राम नरेश यादव, कुलाधिपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर एतद्वारा डॉ. अनिल कुमार सिंह, उप महानिदेशक (प्रा.सं.प्रा.), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् कृषि अनुसंधान भवन-II पूसा, नई दिल्ली-110012 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की कालावधि के लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर का कुलपति नियुक्त करता हूँ।

2. इनकी सेवा शर्ते एवं निबंधन अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत निर्मित परिनियम के अनुसार शासित होंगी।

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

क्र. 7281-2193-अका-विप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5357-2193-अका-विप्र-2012, दिनांक 6 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, मैं भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. कंचन लाल निरापुरे, कराधान सहायक अंकित है के स्थान पर अब कु. कंचन लाल निरापुरे कराधान सहायक पढ़ा जाए।

क्र. 7285-2192-अका-विप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया सम्पन्न हुआ था, जो कि वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये रहता है की अधिसूचना क्रमांक 5104-2192-अका-विप्र-2012, दिनांक 26 जून 2012 को जारी की गई थी, मैं

निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

क्रमांक	नाम अधिकारी	संशोधन
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	

1 कु. कंचन लाल निरापुरे  
कराधान सहायक.

कु. कंचन लता निरापुरे  
कराधान सहायक.

उच्चस्तर  
रवालियर संभाग

2 श्री विजय महाजन  
कराधान सहायक.

श्री विजय श्रीवास्तव  
कराधान सहायक.

क्र. 7287-2200-अका-विप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 4876-2200-अका-विप्र-2012, दिनांक 19 जून 2012 को जारी की गई थी, में शहडोल संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री ओ. पी. गोस्वामी, सहायक वन संरक्षक, अंकित है के स्थान पर श्री ओ. जी. गोस्वामी, सहायक, वन संरक्षक, पढ़ा जाए.

क्र. 7289-2186-अका-विप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-बन विधि (बिना पुस्तकों के) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 5533-2186-अका-विप्र-2012, दिनांक 10 जुलाई 2012 को जारी की गई थी, में जबलपुर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री एस. के. मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, अंकित है के स्थान पर श्री एस. पी. मिश्रा, वनक्षेत्रपाल, पढ़ा जाए.

क्र. 7291-अका-विप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-सिविल पशु चिकित्सा भाग-2 (पुस्तकों सहित) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4429-2012, दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर  
जबलपुर संभाग

1 डॉ. संतोष कुमार डहेरिया पशु चिकित्सा शल्यज्ञ  
2 डॉ. सविता पाण्डेय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ  
3 डॉ. वैशाली घोरमाडे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

रवालियर संभाग

4 कु. पायल जैन पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

क्र. 7293-अका-विप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्नपत्र-सिविल पशु चिकित्सा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) दिनांक 13 अप्रैल 2012 को सम्पन्न हुआ था, का विभागीय पत्र क्रमांक 4440-2012, दिनांक 2 जून 2012 को जारी किया गया था को निरस्त किया जाता है एवं उक्त प्रश्नपत्र में निम्नलिखित परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर  
जबलपुर संभाग

1 डॉ. संतोष कुमार डहेरिया पशु चिकित्सा शल्यज्ञ

निम्नस्तर  
रवालियर संभाग

1 कु. पायल जैन पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

निम्नस्तर  
जबलपुर संभाग

2 डॉ. सविता पाण्डेय पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ  
3 डॉ. वैशाली घोरमाडे पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

क्र. 7295-2199-अका-विप्र-2012-संशोधन.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 मई 2012 एवं अधिसूचना दिनांक 2 जून 2012 को जारी की गई थी, के प्रश्नपत्र प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर  
रीवा संभाग

1 श्री श्रंगार श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर  
2 श्री शैलेन्द्र सिंह डिप्टी कलेक्टर

क्र. 7297-7076-अका-विप्र-2012-संशोधन.—राज्य शासन द्वारा माह जुलाई, 2011 की विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा संचालित की गई थी, की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-89-2011-दोए-3, दिनांक 30 दिसम्बर 2011 के प्रश्नपत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया-द्वितीय में श्री दीपक कुमार वैध, डिप्टी कलेक्टर, जिला हरदा को उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है.

क्र. 7299-2128-अका-विप्र-2012-संशोधन.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 जून -2012 एवं अधिसूचना

क्रमांक 4655-2200-अका-विप्र-2012, दिनांक 11 जून 2012 को जारी की गई थी, में अंशिक संशोधन करते हुए, भोपाल संभाग से सम्मिलित परीक्षा सुश्री तृतीय श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, जिला राजगढ़ प्रश्न पत्र लेखा प्रथम एवं लेखा द्वितीय में, गृह विभाग के नियमानुसार उच्चस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर (श्रम), बैतूल,  
जिला बैतूल (मध्यप्रदेश)

बैतूल, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्र. 1242-48-2012.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, बैतूल, जिला बैतूल, बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता समिति तथा धारा 13 (3) के अंतर्गत अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का पुनर्गठन एतद्वारा करता हूँ :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति जिला बैतूल (म. प्र.)

धारा 13 (2) खण्ड (क) के अनुसार—

1 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बैतूल अध्यक्ष  
जिला बैतूल (म. प्र.).

धारा 13 (2) खण्ड (ख) के अनुसार—

1 श्री बरातीलाल कोरे, मु. पो. पाटाखेड़ा, चिचोली, जिला बैतूल.	सदस्य
2 श्री महेन्द्र सिंह चौहान, मु. कुण्डबकाजन पो. आदर्श दनोरा, भैसदेही.	सदस्य
3 श्री प्रशांत मांडवीकर, गणेश वार्ड सिविल लाईन बैतूल, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (ग) के अनुसार—

1 श्रीमती हेमलता कुंभरे पार्षद मोती वार्ड कोठी बाजार, बैतूल	सदस्य
2 श्रीमती विमला बाई परते, पार्षद, अर्जून वार्ड खंजनपुर, बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (घ) के अनुसार—

1 पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल	सदस्य
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल.	सदस्य
3 सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (2) खण्ड (ड) के अनुसार—

1 प्रबंधक, अग्रणी सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, सदस्य बैतूल.

1. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग बैतूल

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अध्यक्ष बैतूल (म. प्र.).

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

1 श्रीमती ममता बाई भट्ट, दुर्गा वार्ड, बैतूल	सदस्य
2 श्री बाबूलाल जौन्जारे, मु. पो. बांसपानी, तह. जिला बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

1 श्री पूरन साहू, मु. शंकर नगर, बैतूलगंज बैतूल.	सदस्य
2 श्रीमती ममता यादव, पार्षद, सदर बैतूल	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (घ) के अनुसार—

1 तहसीलदार, बैतूल	सदस्य
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चिचोली.	सदस्य
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, बैतूल.	सदस्य

धारा 13 (3) खण्ड (ड) के अनुसार—

1 प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, बैतूल.	सदस्य
---	-------

2. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, शाहपुर

धारा 13 (3) खण्ड (क) के अनुसार—

1 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाहपुरा (म. प्र.).	अध्यक्ष
---	---------

धारा 13 (3) खण्ड (ख) के अनुसार—

1 सज्जन सिंह उइक, (विधायक) वि. स. क्षेत्र घोड़ाडोंगरी, बैतूल.	सदस्य
---	-------

2 श्री दीपक उइके, (अध्यक्ष ज. पं.), मु. पो. घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

3 श्री मनोहर चौरे, मु. पो. शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

धारा 13 (3) खण्ड (ग) के अनुसार—

1 श्री संतलाल हनोते, मु. पो. देशावाड़ी शाहपुर जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

2 श्री सतीष मिश्रा, मु. पहावाड़ी, तह. शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( घ ) के अनुसार—**

1 तहसीलदार, शाहपुर जिला बैतूल	सदस्य
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
3 थाना प्रभारी, शाहपुर, जिला बैतूल	सदस्य
4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, घोड़डोंगरी.	सदस्य

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( झ ) के अनुसार—**

1 शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( च ) के अनुसार—**

1 परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास, शाहपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

**3. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, मुलताई****धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( क ) के अनुसार—**

1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), मुलताई ( म. प्र.).	अध्यक्ष
---	---------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( ख ) के अनुसार—**

1 श्री बाबूराव पाटिल, मु. पो. बिरुल बाजार, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य
2 श्रीमती लक्ष्मी बाई माहोरे, गांधी वार्ड, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य
3 श्री श्रवण हेमराज नागले, मु. ताप्ती वार्ड, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( ग ) के अनुसार—**

1 श्री बलराम सिंग वर्मा, ( अधिवक्ता ) मु. पो. मोरखा, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य
2 श्रीमती संगीता पिपरदे, जनपद अध्यक्ष मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( घ ) के अनुसार—**

1 तहसीलदार, मुलताई, जिला बैतूल	सदस्य
2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुलताई.	सदस्य
3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आमला.	सदस्य

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( झ ) के अनुसार—**

1 शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, तह. मुलताई, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( च ) के अनुसार—**

1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी,, ज. पं. प्रभात-पट्टन, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

**4. अनुविभागीय स्तरीय सतर्कता समिति अनुविभाग, भैंसदेही****धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( क ) के अनुसार—**

1 अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), भैंसदेही ( म. प्र.).	अध्यक्ष
---	---------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( ख ) के अनुसार—**

1 श्री सुनिल भलावी, जनपद अध्यक्ष, भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

2 श्रीमती फूलवती बाई, मु. पो. रतनपुर, वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

3 श्री कुन्दन राठौर, मु. पो. चुनालोमा, वि. ख. भीमपुर, तह. भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( ग ) के अनुसार—**

1 श्री विजय शुक्ला, मु. पो. रतनपुर, वि. ख. भीमपुर, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

2 श्री ब्रह्मदेव कुबडे, वार्ड क्र. ९, भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( घ ) के अनुसार—**

1 तहसीलदार, भैंसदेही, जिला बैतूल	सदस्य
----------------------------------	-------

2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

3 परियोजना प्रशासक, आई. टी. डी. पी., भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( झ ) के अनुसार—**

1 शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा भैंसदेही, जिला बैतूल.	सदस्य
---	-------

**धारा 13 ( ३ ) खण्ड ( च ) के अनुसार—**

1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, आठनेर, जिला बैतूल.	सदस्य
--	-------

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर,

**कार्यालय, कमिशनर, जबलपुर संभाग, जबलपुर**

जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

पत्र क्र. 894-पांच-२-२०१२.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 के नियम 204 के अन्तर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिक निगम, जबलपुर के सीमा क्षेत्र में स्थित पं. द्वारका प्रसाद मिश्र बस स्टेण्ड ( तीन पत्ती चौक के निकट ) से बस स्टेण्ड संचालन को तत्काल प्रभाव से प्रतिषेध किया जाता है तथा निमानुसार दो स्थानों को बस स्टेण्ड के संचालन हेतु एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :—

1. दमोह नाका चौक के निकट स्थित पं. ओंकार प्रसाद तिवारी बस स्टेण्ड ( ख. नं. 33 रुक्का 2.146 है.)

2. मेडिकल कालेज तिराहे के निकट स्थित नगर निगम स्वामित्व की भूमि खसरा क्र. 310 का भाग 14,040 वर्गफीट.

दीपक खाण्डेकर,  
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, जबलपुर.

## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

सागर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्र.-क-6952-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र.-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये उजनेठी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			पटवारी हल्का नंबर	क्षेत्रफल लगभग (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
सागर	शाहगढ़	डिलौना	43	0.67	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/सं.) संभाग, सागर (म. प्र.)	उजनेठी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम डिलौना की भूमि का भू-अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—उजनेठी-पाटन मार्ग निर्माण हेतु।

(3) भूमि का पूरक नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, बण्डा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

हरदा, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्र. 9164-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			क्षेत्रफल (हे. में.)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
हरदा	हंडिया	जोगाखुर्द	7.349	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से।	

क्र. 9166-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	कालीसराय	4.416	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9168-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	भैसवाड़ा	12.685	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9170-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हरदा	हंडिया	सिरालिया	11.658	भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

क्र. 9172-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सर्व संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5 “क” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हें. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1) हरदा	(2) हंडिया	(3) महेन्द्रगांव	(4) 4.669	(5) भू-अर्जन अधिकारी, जिला हरदा	(6) इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262 मीटर पानी भराव किये जाने से.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सुदाम खाडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 561-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12-5266.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		का वर्णन
(1) शहडोल	(2) सोहागपुर	(3) धमनीकला	(4) 1.503	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	(6) धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीकला की निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 562-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12-5267.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	धमनीखुर्द	1.472	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	धमनी सिंचाइ योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीखुर्द की निजी भूमि का अर्जन।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है।

क्र. दस-भू-अर्जन-फा 563-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12-5268.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	कदौहा	3.453	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	धमनी सिंचाइ योजना के नहर में प्रभावित ग्राम कदौहा की निजी भूमि का अर्जन।

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल मध्यप्रदेश में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 6795-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	अन्तर्गत प्राधिकृत	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चांद	साजपानी ब. नं. 272, प. ह. नं. 39, रा. नि. मं. चांद	रकबा 0.260 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग से तु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	सांख हलालखुर्द मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग से तु संभाग सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग से तु निर्माण उपसंभाग छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।				

क्र. 6796-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रलीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन	अन्तर्गत प्राधिकृत	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिंदवाड़ा	चांद	पिपरियाखाती ब. नं. 167, प. ह. नं. 40, रा. नि. मं. चांद	रकबा 0.543 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियाँ।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग से तु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	टॉप बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।				

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 6797-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			(1)	(2)	(3)	(4)
छिन्दवाड़ा	चांद	टॉप, ब. नं. 111, प. ह. नं. 40, रा. नि. मं. चांद.	रक्का 0.413 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां।	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	टॉप-बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।					
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।					
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।					
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।					

क्र. 6798-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. मे.)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	चांद	बांसखेड़ा, ब. नं. 205, प. ह. नं. 42/90, रा. नि. मं. चांद.	रकबा 0.745 एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी जिला सिवनी (म. प्र.).	टॉप-बांसखेड़ा मार्ग में पेंच पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।				
(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग सिवनी, जिला सिवनी (म. प्र.) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।				
(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उपसंभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।				
(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।				
				मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 सितम्बर 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. 1529-12-पत्र क्र. . . . भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	नरवार कला	0.335	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मैहर, जिला सतना।	नरवार तालाब योजना हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्र. 2794-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

**अनुसूची**

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) चुरहट	(3) सांडा (शिवराजपुर)	(4) 4.45	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	(6) दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2796-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

**अनुसूची**

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) सीधी	(2) चुरहट	(3) दुअरा	(4) 7.37	(5) कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	(6) दुअरा माइनर नहर के निर्माण बावत्

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2815-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं।

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सिरमौर	दुलहरा पवाई	1.900	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं.-3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2817-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं।

### अनुसूची

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का विवरण		धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सिरमौर	राजगढ़	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत दुलहरा सब माइनर नं.-3 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2819-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं।

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	सगौना	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में दुलहरा माइनर के अंतर्गत सगौना सब माइनर नं.-2 भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2831-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	पटेहरा	0.340	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2833-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन

यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बरहा 345	(4) 0.720	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2835-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बरहा 344	(4) 3.120	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2837-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1) रीवा	(2) सिरमौर	(3) बगढ़ा 338	(4) 3.200	(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	(6) क्योटी नहर प्रणाली हेतु कटकी उपशाखा नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,**  
**राजस्व विभाग**  
**बड़वानी, दिनांक 10 सितम्बर 2012**

क्र. 1562-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 36-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	खुटवाड़ी	3.672	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु।
योग . .				<u>3.672</u>	

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1561-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 37-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	केरमला	2.019	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु।
योग . .				<u>2.019</u>	

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

बड़वानी, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र. 1599-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 40-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	बलवाड़ी	0.703	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>0.703</u>		

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1598-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 41-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	वरला	वरला	1.125	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.	टोरी तालाब की नहर निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>1.125</u>		

**नोट:**—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी, एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, उप संभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जबलपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2012

प्र. क्र.-04-अ-82-भू-अर्जन-जबलपुर-सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	भेड़ाधाट	0.06 प.ह.नं. 24, न.ब. 355.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद् भेड़ाधाट, जबलपुर.	रोड़ का निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4) निजी भूमि	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	गंभीर उबारी	20.37	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा।	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर ढूब से प्रभावित होने के कारण।

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3, में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1) खण्डवा	(2) हरसूद	(3) सोमगांव खुर्द	(4) निजी भूमि 24.49	(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा.	(6) इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर ढूब से प्रभावित होने के कारण,

**नोट:**—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्रमांक 3, में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**  
डिण्डौरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. भू-अर्जन-118-(अ-82) 2011-12-455.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर		
(1) डिण्डौरी	(2) डिण्डौरी	(3) किकरिया, प.ह.नं. 57, रा.नि.मं. समनापुर.	(4) निजी भूमि— 301 300/1 300/2 299 272/2 272/1 270/1 270/2 269 192	(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	(6) रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु।
			0.136 0.048 0.040 0.092 0.020 0.020 0.016 0.016 0.132 0.112		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			189	0.176	
			147	0.008	
			149/1	0.022	
			149/2	0.022	
			150	0.128	
			151/1	0.060	
			151/2	0.068	
			152	0.016	
			153/1	0.046	
			153/2	0.046	
			153/3	0.046	
			142	0.112	
			143/1	0.040	
			143/2	0.040	
		योग . .	<u>1.462</u>		
		शासकीय भूमि			
		271, 268,	<u>0.144</u>		
		महायोग . .	<u>1.606</u>		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-119-(अ-82) 2011-12-455.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नम्बर		
				द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिण्डौरी	डिण्डौरी	रनगांव	निजी भूमि—	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी	रनगांव जलाशय बायीं तट नहर कार्य हेतु।
		प.ह.नं. 58	302	0.044	
		रा.नि.मं.	289	0.016	
		समनापुर	287/1	0.025	
			287/2	0.025	
			287/3	0.025	
			287/4	0.025	
			287/5	0.025	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		287/6	0.025		
		287/7	0.025		
		282	0.030		
		284	0.128		
		285	0.060		
		250/1	0.108		
		250/2	0.108		
		249	0.048		
		248/1	0.005		
		248/2	0.005		
		248/3	0.005		
		238	0.128		
		237	0.068		
		233/1	0.034		
		233/2	0.034		
		233/3	0.034		
		233/4	0.034		
		227/1	0.005		
		227/2	0.005		
		226	0.028		
		225	0.108		
		224	0.020		
		223	0.048		
		218	0.100		
		215/1	0.034		
		215/2	0.034		
		214	0.024		
		213	0.064		
		182	0.052		
		181	0.024		
		179/1	0.068		
		179/2	0.068		
		योग . .	<u>1.746</u>		
		शासकीय भूमि			
		180, 219	0.042		
		महायोग . .	<u>1.788</u>		

(2) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
शिवपुरी, दिनांक 20 सितम्बर 2012**

क्र. 1528-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			खसरा नम्बर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकमा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
शिवपुरी	नरवर	दावरअली	49 50 51 54 योग .	0.15 0.22 0.03 0.20 <u>0.60</u>	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दांया तट नहर संभाग करैरा, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना उकायला उच्च- स्तरीय दांयी तट (लालपुर पिक- अप विभाग के पश्चात्) से निकलने वाली वितरिका डी-7 के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. 2905-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सेमरिया	कपसा	0.281	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहठ सब माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2907-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	रहट	2.177	कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना अन्तर्गत चचाई वितरक नहर के रहट माझनर में आने वाली भूमि के लिए भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2911-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमोर	नदना	1.551	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	नेवूहा वितरक नहर के निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव।

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
**राजस्व विभाग**

शाजापुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 8-अ-82-2010-11 क्र. 309-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि /परिसम्पत्ति की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि /परिसम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
- (ख) तहसील—बड़ौद
- (ग) ग्राम—मदकोटा (नलिया खेड़ा)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —दूब में आ रहे 27 कच्चे पक्के मकान.

सर्वे नम्बर	अर्जनीय रकबा/ परिसम्पत्ति
-------------	------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

शासकीय भूमि	0.35 हैक्टे. में स्थित
सर्वे नं. 110	ग्राम आबादी की
ग्राम आबादी	परिसम्पत्ति 27 कच्चे/ पक्के मकान 27 नं.

**नोट।—**(1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि/परिसम्पत्ति की आवश्यकता है,—कछाल मध्यम तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से दूब में आने वाली ग्राम आबादी (मकान) अधिग्रहण बाबत्,

(2) भूमि/आबादी के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्र. 6793-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—उमरेठ
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम आंबाझिरी,  
प. ह. नं.-02,  
ब. नं.-01,  
रा. नि. मंडल-उमरेठ।
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—09.816  
हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

प्रस्तावित खसरा	प्रस्तावित रकबा
-----------------	-----------------

नम्बर	(हेक्टेयर में)
-------	----------------

नम्बर	(2)
(1)	
1/3	0.130
4/2	0.934
1/4	0.386
4/5	0.190
18/3	0.454
1/5	0.400
4/6	0.400
1/6	0.290
4/3	0.091
18/1	0.165
1/7	0.555
1/8	0.010
1/9	0.006
4/8	0.091
18/6	0.267
2/1	0.162

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 6794-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनसची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—उमरेठ

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—दबक जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा), जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरांग व परियोजना शीर्ष कार्य उप संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)
खरगोन, दिनांक 17 सितम्बर 2012	31/2	0.526
क्र. 246-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 11-आ-82-2011- 12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	32/1 32/2 32/3 32/4 33/1 33/2 34 35 39/2 40/1 40/2 40/3 40/4 40/5 40/6 40/7 40/8	0.672 0.809 0.809 0.672 2.297 2.305 0.350 0.090 0.820 0.190  0.809 1.178 0.963
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—		
(क) जिला—खरगोन	40/9	0.405
(ख) तहसील—बड़वाह	41	0.202
(ग) ग्राम—ससल्या खुर्द	44	0.709
(घ) लगभग क्षेत्रफल—60.809 हेक्टर.	45	0.607
खसरा नम्बर	रकबा	
	(हे. में)	
(1)	(2)	
7/3	0.130	0.518
10/2	0.070	1.349
17	0.920	0.405
18	0.085	1.350
19	0.165	1.493
21	0.971	1.874
22	4.617	0.829
24	0.506	1.639
25/1	0.344	0.595
25/2	1.518	0.075
25/3	0.392	0.010
25/4	0.486	0.215
27	3.658	0.630
28/1	0.291	0.060
28/2	0.392	0.435
28/3	0.243	1.417
28/4	0.154	1.692
29	2.023	1.693
30/1	0.583	0.809
30/2	0.591	1.618
30/3	0.583	0.809
31/1	0.526	0.223

(1)	(2)	(1)	(2)
76/2	1.043	4/1	1.886
76/3	1.271	4/2	4.071
77	0.999	4/3	2.978
79	1.092	4/4	0.081
81/5	0.770	5/1	0.922
81/6	0.060	5/2	1.032
81/7	0.080	5/3	0.089
81/8	0.290	5/4	0.200
82/1	0.610	6/1	1.076
82/2	0.550	6/2	1.263
82/3	0.205	6/3	1.267
87	0.060	7	0.809
90/1	0.380	8	1.377
योग . .	<u>60.809</u>	9	1.942
		11	0.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्धवहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के रिजरवायर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ऑकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मंडलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 245-भू-अ.-2012-प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—बड़वाह
- (ग) ग्राम—ससल्या बुजुर्ग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—66.907 हेक्टर।

खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
2	0.461
3	1.943

12	1.109
13/1	0.227
13/2	5.702
13/3	0.453
13/4	0.373
13/5	0.429
13/6	0.429
13/7	0.639
14/1	0.886
14/2/1	0.669
14/2/2	0.809
14/3	1.910
14/4	0.425
14/5	0.809
14/6	0.203
14/7	0.202
14/8	0.089
15/1	1.521
15/2	1.522
16/1	0.668
16/2	0.567
16/3	0.567
16/4	0.946
16/5	0.364
16/6	0.344
16/7	0.344
17	0.137
19	0.243
20	3.432

(1)	(2)	(2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
21	2.234	
22	2.804	
23/1	0.539	
23/2	0.270	
26	0.934	
27/1	0.947	(1) भूमि का वर्णन—
27/2	0.526	(क) जिला—खरगोन
28/1	0.850	(ख) तहसील—महेश्वर
28/2	0.769	(ग) ग्राम—गढी
29/1	0.939	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.154 हेक्टर।
29/2	0.939	खसरा नम्बर रकबा
30	0.243	(हे. में)
31	1.769	(1) (2)
33	0.761	
48	0.024	1 0.154
49	0.024	
50	0.024	
66/3	0.050	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
66/4	0.250	
66/6	0.570	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
67	1.455	
68/1	0.225	
68/2	0.075	
69	0.030	
70	0.460	
71	0.572	क्र. 241-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
72/1	0.650	
72/2	0.217	
72/3	0.245	
योग . .	<u>66.907</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के रिजरवायर एवं मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, ऑकारेश्वर/महेश्वर परियोजना बड़वाह एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20 मण्डलेश्वर, के कार्यालय में, अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 243-भू-अ.-2012-प्र. क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—गढी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.154 हेक्टर।

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1

0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर परियोजना द्वितीय चरण की दांयी तट मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 241-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—समसपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.235 हेक्टर।

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1/2

0.310

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
2	0.480		
4/1/1/1	0.790	(1)	(2)
4/1/2	0.280	40/1	0.075
6/1	0.470	40/2	
6/2	0.580	41/1	0.060
6/3	0.550	43/1/1	0.440
55/2	1.240	43/1/2/1	0.690
56/2		43/2/2/1	
57/1	0.475	43/1/2/2	0.900
58/1		43/2/2/2	
55/1		44	0.121
56/1	0.380	51	0.010
57/5		53	0.230
58/2	0.200	54	0.280
60/1	0.800	55/1	-
60/2	1.030	56/1	0.279
61	0.140	57	0.150
62/2	0.510	58	0.700
कुल रकबा . .	<u>8.235</u>	64/1	0.830
		64/2	0.500
		64/3	0.050

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकॉरेश्वर उद्धवहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 239-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—मोहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—26.972 हेक्टर।

(1)	(2)	(3)
338/3	0.160	भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
342/1/2	0.708	
342/1/3	0.260	
355/1	0.380	
355/2	0.550	
356/1/2	0.650	क्र. 240-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 21-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
356/2	2.400	
356/3	0.340	
376/2	0.620	
377	0.194	
358/1	0.090	
358/2	0.165	
358/3/1	0.230	
358/3/2	0.230	
358/4	0.050	अनुसूची
358/5	0.020	
378/476/1	0.526	(1) भूमि का वर्णन—
378/476/3	0.324	(क) जिला—खरगोन
378/476/4	0.264	(ख) तहसील—महेश्वर
378/476/5	0.283	(ग) ग्राम—पाडल्याखुर्द
378/476/6	0.350	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.434 हेक्टर।
378/476/7	0.113	खसरा नम्बर रकबा (हे. में)
378/476/8	0.020	(1) (2)
378/476/9	0.100	107 0.025
378/477	0.081	108 0.198
378/478/1	0.820	109 0.100
378/478/2	0.809	110/4 0.220
394/1	1.214	122 1.142
394/5	1.050	123 0.207
394/11		125 0.032
394/9	0.417	134 0.410
394/10/1		135 0.100
394/10/2	0.417	कुल रकबा . . 1.434
394/10/3	0.417	
394/10/5	0.120	
394/10/6	0.834	
442/1	0.344	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
442/2	0.324	
442/3	0.324	
442/4	0.610	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।
442/5	0.220	
कुल रकबा . . 26.972		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

क्र. 244-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 22-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—हीरापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.215 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
100/2	0.620
102/2	0.860
103/2	0.060
102/3	
103/3	
104	0.410
108/1	0.650
108/3	0.030
132/2/1	0.430
132/2/2	0.450
135/1	0.445
135/2	
135/3	0.525
135/4	0.400
135/5	
136	0.020
137	0.020
138/1	0.135
146	0.160
कुल रकबा . .	<u>5.215</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑंकरेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना,

खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 238-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 23-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—आशापुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—24.196 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
59/4	0.065
59/5	0.344
59/6	0.205
60/2	0.540
61/1	
61/2	0.315
61/3/3	0.035
61/3/4	0.097
61/3/5	0.093
61/3/6	0.089
61/3/7	0.045
61/4/1	0.140
61/4/2	0.170
61/5	0.145
62/2	
61/6	0.160
62/3	
61/7/7	0.025
61/7/8	0.032
61/7/9	0.032
61/7/10	0.024
63/4	
64/4	0.190
65/4	

(1)	(2)	(1)	(2)
75/1	0.140	106	0.260
75/2	0.085	107/3/4ख	
75/3	0.065	106	1.340
75/4	0.140	107/3ख	
75/5	0.050	106	0.075
75/6	0.250	107/3ग	
75/7	0.040	106	0.250
76/1		107/3/1ख	
76/2	0.075	106	0.220
81		107/3/1 ग	
82/3	0.080	106	0.235
83/1	0.325	107/3/2 ग	
83/2	0.050	106	0.280
83/3	0.401	107/3/3	
83/4	0.234	106	0.170
84/3	0.060	107/3/4	
85/3		106	0.180
84/4	0.265	107/3/5	
85/4		106	0.155
86/2	0.230	107/3/6	
127/2		106	0.190
86/4	0.110	107/3/7	
127/4		106	0.170
86/5	0.715	107/3/8	
127/5		106	0.230
86/6	0.571	107/3/9	
127/6		108/1	0.125
86/8	1.255	128	0.049
127/8		131/1	0.240
87/1/2	0.050	131/2	0.243
87/2	0.010	131/3	0.194
87/4	0.010	131/4	0.190
96/3	0.715	131/5	0.133
99/2	0.170	132/1	0.220
101	0.500	132/2	0.100
102	0.450	133/1	
103	0.030	133/2	1.500
104	0.010	133/3	
106	0.150	133/4	
107/3/1ख		134/2/1	0.005
106	0.170	134/2/2	0.010
107/3/2ख		134/3/1	0.015
106	0.325	134/3/2	0.005
107/3/3ख		160/2	0.650

(1)	(2)	(1)	(2)
160/3	0.345	120/1/1	0.070
160/4	0.180	206/4	0.040
161/1	0.275	206/5	0.170
161/2	0.410	207/1	0.705
161/3	1.530	207/2	0.320
161/4	0.275	216	0.330
162/1/9	0.040	214/1	0.730
162/1/14	0.480	215/1	
162/1/15	0.515	217	0.385
162/1/16	0.040	228	0.065
162/2	1.675	229	0.010
213/1	0.410	230	0.015
213/2	0.110	231	0.040
कुल रकबा . .	<u>24.196</u>	232	
		233	0.800
		234	
		235	
		236/2	1.015
		236/3	0.020
		237	0.050
		कुल रकबा . .	<u>4.835</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्धवहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 242-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 24-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—महेश्वर
- (ग) ग्राम—करही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.835 हेक्टर।

खसरा नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

119

0.070

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ऑकारेश्वर उद्धवहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश  
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 09-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
- (ख) तहसील—ग्वालियर
- (ग) ग्राम—गुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.67 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में.)
--------------	------------------------	---

(1)	(2)	(3)
-----	-----	-----

474	0.05	0.02
-----	------	------

475	0.53	0.15
-----	------	------

388	0.65	0.14
-----	------	------

389	0.57	0.11
-----	------	------

390	0.28	0.04
-----	------	------

391	0.64	0.12
-----	------	------

452	0.15	0.04
-----	------	------

453	0.21	0.04
-----	------	------

454	0.35	0.09
-----	------	------

548	0.28	0.09
-----	------	------

551	0.54	0.12
-----	------	------

552	0.50	0.07
-----	------	------

444	0.55	0.02
-----	------	------

443	0.53	0.09
-----	------	------

458	0.09	0.01
-----	------	------

556	0.52	0.09
-----	------	------

558	0.39	0.01
-----	------	------

1126	0.22	0.07
------	------	------

1125	0.13	0.04
------	------	------

1132	0.48	0.16
------	------	------

1121	0.13	0.02
------	------	------

1120	0.55	0.01
------	------	------

561	0.57	0.10
-----	------	------

970	0.15	0.05
-----	------	------

971	0.35	0.06
-----	------	------

	(1)	(2)	(3)
	972	0.02	0.02
	958	0.98	0.24
	951	0.93	0.16
	952	0.30	0.02
	927	0.47	0.16
	932	1.40	0.13
	933	0.45	0.01
	935	0.81	0.12
	1124	0.15	0.02
	549	0.11	0.01
	527	0.24	0.01
	457	0.33	0.01
			योग . . <u>2.67</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—हरसी उच्चस्तरीय नहर की गुरी मायनर शाखा नहर के निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 62-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—गोबर्ड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.770 हेक्टर।

सर्वे नं.	कुल रकबा (हे. में.)	अर्जित किये जाने रकबा (हे. में.)
		(1)
		(2)
		(3)
	400	0.61
	391	0.78
	387	0.29
	390	0.11
	392	0.53

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
393	0.010	0.010	307	0.420	0.010
386	0.25	0.060	308	0.380	0.130
394	0.56	0.020	309	0.860	0.240
385	0.39	0.100	15	1.460	0.260
383	0.31	0.090	251	1.080	0.250
384	0.16	0.040	246	0.650	0.180
382	0.84	0.130	248	0.780	0.170
<b>कुल रकमा . .</b>			150	1.010	0.030

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।	148	0.500	0.180
	145	2.930	0.500
	143	0.380	0.30
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।	107	0.640	0.010
	104	0.310	0.130
	13	2.420	0.420

प्र. क्र. 64-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—ग्वालियर	
(ख) तहसील—ग्वालियर	
(ग) ग्राम—ईकहरा	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.695 हेक्टर।	

सर्वें नं.	कुल रकमा (हे. में.)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकमा (हे. में.)
(1)	(2)	(3)
304	0.200	0.010
253	0.740	0.090
311	1.000	0.060
310	1.360	0.010
305	0.100	0.100
252	0.840	0.110
254	1.200	0.270
255	2.610	0.070
12/1	0.840	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर/रशीदपुर उपशाखा नहर के निर्माण हेतु।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्र. 5056-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

	(1)	(2)
	553	0.03
	554	3.33
		कुल योग . . 39.65

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) ग्राम—कोटरो
- (घ) क्षेत्रफल—39.65 हेक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
426	0.84
427	1.65
552	1.21
556	0.22
561	2.63
568	1.64
569	2.47
693	1.21
42	2.02
591	0.03
601	1.24
602	0.40
640	0.38
656	2.39
655	0.04
673	1.79
680	0.04
555	0.13
558	2.16
566	1.11
567	2.60
592	1.88
605	0.55
557	0.99
484	2.64
507	0.04
508	0.08
562	3.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—महान बांध के डूब क्षेत्र हेतु

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है

क्र. 5058-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त निजी/शासकीय भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—मझौली
- (ग) ग्राम—चुनगुना
- (घ) क्षेत्रफल—12.64 हेक्टर

खसरा नम्बर	अर्जित रकमा (हे. में)
(1)	(2)
53	0.94
55	1.30
665	1.62
750	0.82
757	1.18
758	0.36
130	0.30
733	1.00
114	1.29
139	0.81
238	0.48
178	0.46
714	0.07
740	1.47
247	0.08
715	0.46
	कुल योग . . 12.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—महान बांध के दूब क्षेत्र हेतु,	(1)	(2)	
	89	0.220	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर सीधी के कार्यालय में किया जा सकता है।	93/3	0.100	
	97/3	0.110	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	88 98 100	1.100 0.040 0.200	
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश	101	1.000	
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,	106	0.020	
राजस्व विभाग	110 113	0.030 0.020	
डिण्डौरी, दिनांक 18 सितम्बर 2012	114	0.300	
	115	0.500	
क्र.—भू-अर्जन-107-अ-82-2011-12-453-ए.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	116 117 128/1 128/2 128/3 129 130 467/1 468 469 470 471 473/1 474/1 476 542	0.800 0.300 0.300 0.080 0.330 0.330 0.140 0.100 0.130 0.120 0.400 0.330 0.400 0.060 0.120 0.330	
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—डिण्डौरी	468	0.130	
(ख) तहसील—शहपुरा	469	0.120	
(ग) ग्राम—बिलगांव प. ह.नं. 19	470	0.400	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—22.440 हेक्टर।	471	0.330	
	473/1	0.400	
खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकमा (2)		
157	1.100	541	0.220
154	0.480	543	0.060
153	0.120	544	0.020
158	0.300	545	0.130
92	0.220	540	0.160
91/1	0.340	537	0.210
91/2	0.060	536	0.040
90	0.210	546	0.850
		550	0.100
		551	0.160

(1)	(2)	(ग) ग्राम—सूरजपुरा प.ह.नं. 18 (घ) लगभग क्षेत्रफल—15.190 हेक्टर.
557/1	1.800	खसरा अर्जित रकबा
566/2	0.100	नम्बर (हे. में)
556/1	0.740	(1) (2)
567	0.400	
568	0.120	नहर कार्य निजी भूमि
569	0.400	
571	0.040	3 0.220
614	0.020	7 0.050
617/1	0.370	8 0.090
617/2	0.300	9 0.450
618	0.600	10 0.100
621/1	0.300	29 0.120
613	0.120	30 0.180
698/1	0.040	31 0.160
699	0.460	32 0.400
कुल योग निजी भूमि:	<u>18.50</u>	34 0.100
शासकीय भूमि—		40 0.500
156, 108, 515, 466, 472, 475, 477, 478, 622,	3.940	73 0.100
539, 537, 570, 571, 571, 610, 700		107 1.030
कुल योग :	<u>22.44</u>	70 0.300
		71 0.200
		69 0.430
		66 0.950
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.		60 0.060
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिणडौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		61 0.900
क्र.-भू-अर्जन-108-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	62 0.270	
		55 0.240
		56 0.650
		57 0.090
		58 0.550
		59 0.420
		224 1.100
		230/2 0.200
		253 0.130
		254 0.700
		255 0.300
		256 0.680
		257 0.160
(1) भूमि का वर्णन—		258 0.060
(क) जिला—डिणडौरी		260 0.470
(ख) तहसील—शहपुरा		261 0.150

(1)	(2)	(1)	(2)
263	1.100	84	0.030
264	0.110	82	0.020
265	0.210	80	0.110
267	0.480	79	0.250
267	0.200	78	0.230
कुल योग निजी भूमि:	<u>14.61</u>	77	0.040
शासकीय भूमि—		74	0.080
4, 77, 74, 75, 76,	0.580	144	0.200
231		146	0.110
कुल योग :	<u>15.19</u>	147	0.130
		66/1	0.360
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.		150	0.160
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिप्टी के कार्यालय में किया जा सकता है.		156	0.360
क्र.-भू-अर्जन-109-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		153	0.270
		232/1	0.080
		233	0.160
		236	0.250
		237	0.100
		143/1	0.120
		143/2	0.120
		योग नहर कार्य निजी भूमि:	<u>4.040</u>
शासकीय भूमि—			
104, 105, 107, 133/1,		1.100	
89, 88, 85, 151			
कुल योग :		5.140	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव  
मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत तट नहर कार्य हेतु.  
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी  
डिप्टी के कार्यालय में किया जा सकता है।

खसरा	अर्जित रकम
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
<b>नहर कार्य निजी भूमि</b>	
102	0.050
103	0.200
106	0.020
108	0.140
133/3	0.040
90	0.100
87	0.270
135	0.040

क्र.-भू-अर्जन-110-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन  
को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के  
पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित  
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन  
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत  
इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त  
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—डिप्टी  
(ख) तहसील—डिप्टी

(ग) ग्राम—बिलगांव प.ह.नं. 19	(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.95 हेक्टर.	654	0.400
खसरा	अर्जित रकबा	657
नम्बर	(हे. में)	650
(1)	(2)	647
नहर कार्य निजी भूमि	652	0.590
	651	0.160
701	0.340	653
702	0.450	648
703	1.050	631
704	0.870	641
706/1	0.630	642
604	0.400	649
605/1	0.090	639
607	1.080	605/2
609	0.080	557/2
614	0.680	557/3
568	0.270	कुल योग निजी भूमि: 24.890
616	0.140	शासकीय भूमि—
617/2	0.070	700, 705, 603, 606,
618	0.050	608, 615, 597, 583,
595	0.200	582, 579, 570, 565 ,
581	0.850	622, 643, 638, 572,
580	0.050	573, 574
550	0.100	कुल योग : 31.950
554	0.870	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव
578	0.300	जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.
569	0.290	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी
571	1.750	डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
556	0.200	
699	0.500	क्र.-भू-अर्जन-112-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन
566/2	0.160	को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के
557/1	0.440	पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित
551	0.250	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन
552	0.090	अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत
553	0.090	इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन
555	1.750	के लिये आवश्यकता है:—
549	0.200	अनुसूची
548	0.110	
655/1	0.290	(1) भूमि का वर्णन—
655/2	0.110	(क) जिला—डिण्डौरी
656	0.520	(ख) तहसील—शहपुरा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के शीर्ष कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-112-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—डिण्डौरी

(ख) तहसील—शहपुरा

(ग) ग्राम—अमरेश प.ह.नं. 16  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.770 हेक्टर.

(ग) ग्राम—बरगा प.ह.नं. 64  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—27.361 हेक्टर.

खसरा	अर्जित रक्कब
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

खसरा	अर्जित रक्कब
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

### नहर कार्य निजी भूमि

3	0.400
4	0.250
5	0.300
6	0.200
10	0.300
12/1	0.100
12/3	0.130
12/4	0.100
12/2	0.200
14/1	0.040
कुल योग निजी भूमि:	<u>2.02</u>

### नहर कार्य निजी भूमि

418	0.200
417	1.290
416/6	0.550
416/2	0.410
415	0.300
414	0.310
413/1	0.110
413/2	0.110
413/3	0.110
412	0.580
413/4	0.110
367/2	0.261
367/1	0.261
400/1	0.070
400/2	0.070
401	1.250
402	0.520
403	0.260
405	0.260
406	1.890
395	1.030
396	1.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-113-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—डिण्डौरी

404	0.310
387	3.000
424/1	0.320
424/2	0.320
424/3	0.330
424/4	0.330
424/5	0.330
425	0.900
421	0.690
429	0.540
527	0.180
533	0.540
534/1	0.256

(1)	(2)	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।
534/2	0.256	क्र.-भू-अर्जन-114-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
534/3	0.256	
536	0.161	
537	0.085	
431/1	0.070	
431/2	0.060	
431/3	0.060	
399	0.020	
398	0.020	अनुसूची
427	0.147	
432	0.375	(1) भूमि का वर्णन—
434	0.080	(क) जिला—डिण्डौरी
436	0.057	(ख) तहसील—शहपुरा
435	0.070	(ग) ग्राम—राढो प.ह.नं. 17
437/1	0.050	(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.18 हेक्टर.
437/2	0.050	खसरा अर्जित रकबा
437/3	0.050	नम्बर (हे. में)
439	0.208	(1) (2)
440	0.060	नहर कार्य निजी भूमि
443/2	0.010	45 0.040
443/1	0.010	46 0.370
433/3	0.010	47 0.100
534/1	0.020	50 0.220
534/2	0.020	49/2 0.040
534/3	0.020	99/1 0.100
536	0.010	99/2 0.040
537	0.030	90/3 0.080
538/1	0.060	101 0.060
538/2	0.050	104 0.220
538/3	0.050	535 0.100
535/1	0.020	552 0.220
535/2	0.020	545 0.050
535/3	0.020	546 0.020
कुल योग निजी भूमि:	<u>21.653</u>	544 0.280
शासकीय भूमि—		548 0.470
532, 528, 443, 430, 426, 407, 397, 388, 430, 442, 532	<u>5.708</u>	551 0.220
कुल योग :	<u>27.361</u>	549 0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगा जलाशय (समनापुर) के शीर्ष कार्य हेतु,		555 0.040 5 0.220

(1)	(2)	(1)	(2)
4	0.330	498	0.280
3	0.090	455	0.060
2	0.180	456	0.120
1	0.320	452	0.020
100	0.010	494	0.020
कुल योग निजी भूमि:	<u>3.84</u>	493	0.530
शासकीय भूमि—		497	0.120
142, 102, 543, 527,	0.340	500	0.030
49/1, 132, 336, 542		502	0.960
कुल योग :	<u>4.18</u>	503	0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-115-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिण्डौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—रनगांव प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—11.27 हेक्टर।

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

### नहर कार्य निजी भूमि

412	0.060
424	0.020
459	0.390
496	0.120
425	0.060
457	0.380

शासकीय भूमि—	
461, 460, 411, 413,	
415, 458, 429, 451,	
449, 504, 348, 511,	
328, 200, 189, 203,	
186	
कुल योग :	<u>5.490</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिण्डौरी के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र.-भू-अर्जन-116-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	(1)	(2)	
अनुसूची	306	0.260	
	307	0.350	
	309	0.170	
	310	0.050	
	312	0.280	
	319	0.490	
	320	0.950	
(1) भूमि का वर्णन—	1551	1.050	
(क) जिला—डिणडौरी	1552	0.210	
(ख) तहसील—शहपुरा	1553	0.400	
(ग) ग्राम—बंरगाव प.ह.नं. 16	1558	0.300	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—38.36 हेक्टर.	1559	0.160	
	1571	0.700	
खसरा	अर्जित रकबा	1572	0.700
नम्बर	(हे. में)	1537	0.270
(1)	(2)	1538	0.700
		1536	0.300
नहर कार्य निजी भूमि		1535	0.400
50	1.890	1534	0.220
51	0.210	1533	0.900
52	0.150	1514	0.300
54	0.180	1515	0.200
58	1.230	1517	0.430
60	0.400	1593	0.340
62	0.260	1594	0.560
63	0.720	1595/1	0.200
69	0.960	1595/2	0.100
70	0.200	1595/3	0.100
71	0.400	1601/1	0.100
72	0.200	1601/2	0.360
73	0.520	1601/3	0.150
74	0.520	1605	0.420
300	0.380	1624	0.380
301	0.380	1622	0.300
302	0.360	1609	0.260
304	0.160	1608	0.200
		1613	0.960

(1)	(2)	(1)	(2)
1614	0.080	231	0.100
कुल योग निजी भूमि:	<u>24.42</u>	230	0.020
शासकीय भूमि—		249	0.560
53, 59, 61, 68, 303,		229	0.450
309, 308, 321, 1554,		257/1	0.150
1560, 1562, 1541, 1540,	13.940	251/2	0.150
1570, 1539, 1516, 1604,		258	0.200
1623, 1496, 1612		262	0.060
कुल योग :	<u>38.36</u>	259	0.140
		256	0.130
		260	0.130
		261	0.280

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिणडौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-117-अ-82-2011-12-453.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—डिणडौरी
- (ख) तहसील—शहपुरा
- (ग) ग्राम—मर्गेला प.ह.नं. 43
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—9.60 हेक्टर.

कुल योग निजी भूमि: 9.11

खसरा	अर्जित रकमा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

### नहर कार्य निजी भूमि

168	0.750
169	0.040
235	0.060
234/1	0.310
232	0.400

शासकीय भूमि—

226, 263, 285, 349/1 | 0.490

कुल योग : 9.60

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बिलगांव जलाशय मध्यम सिंचाई परियोजना के नहर कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी डिणडौरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,	(1)	(2)
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं	904	0.02
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	905	0.02
	906	0.02
रीवा, दिनांक 17 सितम्बर 2012	907	0.02
क्र. 2780-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	909	0.02
	910	0.02
	944	0.20
	945	0.24
	946	0.05
	947	0.08
	965	0.28
	966	0.04
	968	0.05
	योग . .	2.11

## (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—सजहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.35 हेक्टेयर.

## (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

717 0.02

735 0.04

736 0.04

843 0.10

845 0.02

902 0.02

योग . . 0.24

योग—(अ+ब) 35 किता रकबा . . 2.35

## घुंटा सब माझनर नहर निर्माण हेतु

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

## (अ) निजी भूमि का विवरण

704	0.02
705	0.02
706	0.03
707/1, 707/2	0.03
709	0.16
774	0.02
775	0.02
830	0.01
832	0.03
834	0.03
837	0.08
847	0.09
848	0.21
890	0.06
897	0.05
903	0.19

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 2.11 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा = 0.24 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2782-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित

किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

1) भूमि का वर्णन—			756	0.13	0.02
(क) जिला—सीधी			757	0.02	0.02
(ख) तहसील—चुरहट			755	0.03	0.01
(ग) ग्राम—साडा शिवराजपुर			751	0.07	0.02
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.89 हेक्टेयर.			791	0.09	0.01
खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	790	0.14	0.03
(1)	(2)	(3)	749	0.10	0.02
			798	0.06	0.02
			799	0.05	0.02
			802	0.07	0.02
			803	0.63	0.06
			823	0.09	0.05
			822	0.12	0.6
			820	0.06	0.04
			821	0.04	0.01
251	0.39	0.09	885	0.11	0.03
252	0.35	0.03	886	0.09	0.03
253	0.40	0.07	898	0.09	0.02
277	0.15	0.04	897	0.05	0.01
275	0.55	0.10	899	0.08	0.03
276	0.48	0.11	895	0.13	0.02
228	0.40	0.04	927	0.06	0.02
227	0.13	0.05	928	0.09	0.02
230	0.86	0.06	957	0.12	0.03
231	0.19	0.04	959	0.08	0.03
250	0.75	0.07	989	0.18	0.04
171	0.70	0.04	986	0.16	0.02
172	0.48	0.02	988	0.03	0.03
173	0.27	0.06	997	0.290	0.07
175	0.92	0.12	996	0.16	0.04
176	0.18	0.01	995	0.07	0.03
301	0.11	0.01	1065	0.07	0.04
302	0.05	0.02	1066	0.06	0.03
303	0.13	0.01	1067	0.08	0.04
304	0.16	0.01	1068	0.04	0.03
305	0.10	0.05	1027	0.08	0.04
308	0.13	0.08	1047	0.11	0.04
316	0.35	0.02	1048	0.22	0.07
317	0.59	0.13	1076	0.11	0.02
300	0.13	0.01	1123	0.05	0.01
299	0.16	0.04	1124	0.04	0.03
274	0.47	0.06	1153	0.07	0.03
273	0.08	0.02	1152	0.02	0.01
754	0.07	0.02	1150	0.02	0.01
759	0.14	0.02	625	0.14	0.02
760	0.630	0.05		योग . .	22.07
					2.80

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
		(ब) म. प्र. शासन की भूमि :			
229	0.07	0.02	589/1	0.053	0.016
307	0.17	0.07	589/2	0.011	
योग . .	<u>0.24</u>	<u>0.09</u>	588/1	0.020	0.010
			588/2	0.220	
			598/1	0.303	0.018

(अ) निजी भूमि 76 किता 2.80 हे.	598/2	0.049
(ब) शासकीय भूमि 2 किता 0.09 हे.	671/1	0.693
योग . . 78 किता <u>2.89</u> हे.	671/2	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.	672	0.081	0.015
	384/1	0.150	0.025

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	384/2	0.060	
	397	0.129	0.030
	396	0.093	0.038
	395	0.328	0.050

क्र. 2784—भू—अर्जन—2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	394	0.150	0.032
	391/1	0.057	0.050
	391/2	0.113	
	391/3	0.125	
	387/1	0.089	0.030
	387/2	0.057	
	673/1	0.017	0.005
	673/2	0.070	
	678	0.016	0.013
	680	0.093	0.010
	684	0.134	0.024
	685	0.624	0.050
	687/1	0.042	0.029
	687/2	0.029	
	688/1	0.178	0.027

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी	688/2	0.045
(ख) तहसील—चुरहट	689	0.202
(ग) ग्राम—नक्वेल	665	0.129
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.856 हेक्टेयर.	696	0.089

खसरा क्र.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	708	0.299	0.113
(1)	(2)	(3)	710	0.065	0.006
			831	0.283	0.035

## (अ) निजी भूमि का विवरण :

393	0.190	0.028	827	0.069	0.023
392	0.138	0.027	828	0.117	0.016
580	0.073	0.033	652	0.304	0.010
583/1	0.166	0.050	653	0.049	0.010
583/2	0.043		695	0.053	0.024
584/1	0.100	0.060	669/1	0.065	0.020
584/2	0.208		669/2	0.016	
			669/3	0.016	
			669/4	0.178	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
944	0.057	0.023	650/1821	0.032	0.010
945	0.061	0.012	650/1820	0.045	0.011
940	0.040	0.020	802/1892	0.024	0.023
912/1	0.092	0.020	579/1741/1	0.020	
912/2	0.012		579/1741/2	0.060	0.045
914	0.020	0.010	580/1743	0.089	0.010
670/1	0.065	0.042	584/1747	0.057	0.016
670/2	0.162		586/1751	0.045	0.022
670/2क	0.105		586/1752	0.040	0.010
670/3	0.146		386/1626	0.113	0.040
670/2ख	0.072		386/1627	0.073	0.013
924	0.024	0.010	386/1628/1	0.056	0.030
932	0.024	0.010	386/1628/2	0.056	
933	0.028	0.010	707/1844	0.049	0.010
967	0.117	0.005	941	0.028	0.016
910	0.049	0.010	650/1818	0.040	0.026
915	0.024	0.021			
916	0.024	0.020	कुल योग . .	10.635	1.851
917	0.024	0.005			
918	0.053	0.010			
919	0.053	0.012			
920/1	0.037	0.010	968/1967		0.05
920/2	0.024		महायोग : अ+ब=115 किता . .		1.856
921	0.073	0.013			
922/1	0.037	0.013			
922/2	0.036				
977/1	0.125	0.015			
977/2	0.045				
832	0.162	0.032			
940/1955	0.020	0.020			
942/1957	0.016	0.015			
933/1948	0.020	0.010			
927/1947	0.024	0.010			
184	0.077	0.005			
406/1643	0.178	0.012			
407/1644	0.008	0.006			
968/1967/2	0.016				
843	0.040	0.010			
844	0.024	0.013			
845	0.0120	0.005			
670/1830/1क	0.129	0.020			
670/1830/2क	0.020				
668/1827	0.081	0.027			
664/1823	0.020	0.020			

## ( ब ) शासकीय भूमि

968/1967  
महायोग : अ+ब=115 किता . .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि, शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2786-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—झाझा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.19 हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.12 हेक्टेयर.  
 घुंघुटा सब माइनर ग्राम—घुंघुटा

खसरा	रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1.)	(2.)

## (अ) निजी भूमि का विवरण

2247/1, 2247/2	0.02
2248	0.05
2249	0.04
2255	0.08
योग . .	<u>0.19</u>

## (ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग—(अ+ब) 4 किता . .	<u>00</u>
	<u>0.19</u>

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . . 0.19 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2788-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—घुंघुटा

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

## (अ) निजी भूमि का विवरण

254	0.03
255	0.06
256	0.09
257	0.03
262	0.03
263	0.05
266	0.08
267	0.03
280	0.07
295	0.05
296	0.03
297	0.08
298	0.04
299	0.04
340	0.05
341	0.05
351	0.07
354	0.07
357	0.02
358	0.18
377	0.06
378	0.01
430	0.04
431	0.04
432	0.02
433	0.02
434	0.01
435	0.02
436	0.02
849	0.07
853	0.09
863	0.02
924	0.01
925	0.08
926	0.06
योग (अ) . .	<u>2.73</u>

## (ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :

248	0.03
-----	------

(1)	(2)
351	0.03
353	0.06
355	0.02
359	0.02
363	0.07
541	0.03
617	0.02
619	0.02
854	0.09
योग—(ब) . .	<u>0.39</u>
योग—(अ+ब) . .	<u>3.12</u>

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . . 2.73 हे.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . . 0.39 हे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2790-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—रामपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.58 हेक्टेयर।

### हरिहरपुर सब माइनर ग्राम-रामपुर

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)

### (अ) निजी भूमि का विवरण

296	0.16
338/1, 338/2, 338/3	1.16
योग (अ) . .	<u>1.32</u>

(ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :	
336	0.02
365	0.18
366	0.06
योग—(ब) . .	<u>0.26</u>
योग—(अ+ब) . .	<u>1.58</u>

प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . . 1.32 हे।

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . . 0.26 हे।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2792-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—भितरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.22 हेक्टेयर।

### भितरी सब माइनर ग्राम-भितरी

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
2478	0.16
2479	0.16
2481	0.06
2482	0.23

(1)	(2)	(1)	(2)
2483	0.13	2997	0.18
2484	0.07	2999	0.34
2515	0.10	3000	0.10
2527/1/1, 2527/1/2		3007	0.01
2527/2, 2527/3		3008/1, 3008/2	0.18
2527/4, 2527/5,	0.07	3009	0.01
2527/6		3029	0.05
2528	0.07	3038	0.20
2529	0.02	3040	0.04
2530/1/1, 2530/1/2		3042/1, 3042/2	0.08
2530/2, 2530/3		3043/1, 3043/2	0.05
2530/4, 2530/5	0.01	3047/1	
2530/6		3047/2	0.07
2531	0.13	3047/3	
2532	0.03	3049/1, 3049/2	0.31
2533	0.01	3051	0.03
2535	0.08	3052	0.10
2536	0.01	3053	0.06
2551/1, 2551/2		3055/1, 3055/2	0.07
2551/3, 2551/4	0.01	3060	0.02
2552/1, 2552/2		3063/1, 3063/2	0.01
2552/3, 2552/4	0.02	योग (अ) . .	<u>4.19</u>
2553/1, 2553/2			
2553/3, 2553/4	0.14		
2554/1, 2554/2	0.01	2619	0.01
2555/1, 2555/2	0.02	2637	0.02
2557/1, 2557/2		योग—(ब) . .	<u>0.03</u>
2557/3, 2557/4	0.01	योग—(अ+ब)= 51 किता . .	<u>4.22</u>
2560/1, 2560/2	0.01		
2561/1, 2561/2	0.16	प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण . .	4.19 है.
2562	0.04	प्रस्तावित शासकीय भूमि का रक्कम . .	0.03 है.
2629/1/1		योग :	<u>4.22 है.</u>
2629/1/2			
2629/1/3	0.08		
2630	0.17		
2635/1, 2635/2			
2635/3, 2635/4	0.13		
2636/1, 2636/2			
2636/3, 2636/4	0.10		
2638/1, 2638/2			
2638/3, 2638/4	0.04		
2638/5			

## (ब) म.प्र. शासन की भूमि का विवरण :

2619 0.01

2637 0.02

योग—(ब) . . 0.03योग—(अ+ब)= 51 किता . . 4.22

प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण . . 4.19 है.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रक्कम . . 0.03 है.

योग : 4.22 है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2798-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		(1)	(2)
(क) जिला—सीधी		639	0.01
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन		640	0.02
(ग) ग्राम—झाझ		647	0.15
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.70 हेक्टेयर.		648	0.04
		650	0.04
		655	0.02
		664	0.11
		720	0.11
		721	0.09
		722	0.02
		527/3819ख	0.01
		770/3820	0.02
		योग (अ) . .	<u>1.70</u>

## पटेल टोला माइनर ग्राम-झाझ

खसरा अर्जित रकबा

नम्बर (हे. में)

(1) (2)

## (अ) निजी भूमि का विवरण

516 0.02

517 0.14

518 0.03

519 0.04

544 0.01

548 0.03

549 0.02

550 0.03

553 0.03

554 0.02

562 0.06

564 0.07

565/1, 565/2, 565/3 0.06

569 0.01

570 0.05

571 0.02

572 0.01

575/1, 575/2 0.04

576 0.05

594 0.02

600/1, 600/2 0.03

623 0.08

637 0.04

638 0.06

## (ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण-शून्य

योग—(ब) . . 00

योग—(अ+ब) . . 1.70

प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण . . 1.70 है.

प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . . निरंक

योग : 1.70 है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2800-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

## अनुसूची

## (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—डिठौरा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.08 हेक्टेयर.

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

खसरा	रकबा	अनुसूची	
नम्बर	(हे. में)		
(1)	(2)	(1) भूमि का वर्णन—	
(अ) निजी भूमि का विवरण			
286	0.03	(क) जिला—सीधी	
237	0.07	(ख) तहसील—रामपुर नैकिन	
288	0.08	(ग) ग्राम—रायखोर	
314	0.08	(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.01 हेक्टेयर.	
315	0.05	खसरा	अर्जित रकबा
316	0.05	नम्बर	(हे. में)
320	0.05	(1)	(2)
340	0.04	(अ) निजी भूमि का विवरण	
341	0.10	100	0.02
342	0.05	113	0.02
347	0.08	126	0.09
348	0.05	128	0.03
349	0.02	129	0.01
357	0.03	132	0.03
360	0.01	133	0.03
361	0.10	134	0.01
362/1, 362/2	0.08	136	0.03
363	0.08	137	0.02
364	0.04	138	0.02
योग (अ) . .	<u>1.08</u>	139	0.05
गासकीय भूमि का रकबा	0	140	0.03
निजी भूमि का रकबा . .	<u>1.08</u>	141	0.01
जिनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर		152	0.06
योजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस		153	0.05
स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		160	0.01
य का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर		199	0.02
योजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।		200	0.02
प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात		205	0.04
दो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में		206	0.01
, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक		207	0.03
ये आवश्यकता है: अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894		208	0.02
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा		210	0.03
		212	0.06
		213	0.02
		214	0.07
		237	0.02
		263	0.05

(1)	(2)	(1)	(2)
264	0.02	(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण :	
265	0.02	196	0.02
267	0.07	238	0.04
269	0.03	1657	0.02
270	0.03	योग—(ब) . .	0.08
271	0.02	योग—(अ+ब) . .	<u>3.01</u>
272	0.08		
273	0.10	प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा . .	2.93 हे.
276	0.03	प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा . .	0.08 हे.
277	0.05		महायोग : <u>3.01 हे.</u>
278	0.01		
279	0.02	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।	
280	0.02		
309	0.02		
314	0.01		
315	0.08	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	
318	0.02		
1604/1, 1604/2	0.05		
1607/1 } 1607/2 } 1607/3 }	0.04	क्र. 2805-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—	
1608	0.07		
1609	0.04		
1612	0.04		
1613	0.05		
1620/1, 1620/2	0.11		अनुसूची
1621	0.03	(1) भूमि का वर्णन—	
1622	0.04	(क) जिला—रीवा	
1623	0.03	(ख) तहसील—सिरमौर	
1624	0.04	(ग) ग्राम—टाटा कोठार	
1627/1, 1627/2	0.04	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.016 हेक्टेयर।	
1628	0.03		
1632	0.07	खसरा	अर्जित रकबा
1633	0.18	नम्बर	(हेक्टेयर में)
1640	0.06	(1)	(2)
1641	0.01	185	0.016
1642	0.01	योग . .	<u>0.016</u>
1658	0.24		
1672/1, 1672/2 } 1672/3, 1672/4 }	0.21	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत महरी माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।	
योग (अ) . .	<u>2.93</u>		

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2807-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—उमरी कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.237 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 2531 2534 2535 2589 3031 3197 3546 3837 3870 4053 4092 4094 4150	खसरा नम्बर (1)
	0.030	101
	0.008	102
	0.024	103
	0.008	
	0.011	
	0.008	
	0.012	
	0.026	
	0.012	
	0.048	
	0.028	
	0.006	
	0.016	
योग . .	0.237	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2809-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—भेड़रहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.142 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) 101 102 103	(2)
	0.084	
	0.039	
	0.019	
योग . .	0.142	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2811-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—जामू 177	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.072 हेक्टेयर.	
खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
487	0.072
योग . .	<u>0.072</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शाहपुर माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2813-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—गहनौआ
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.160 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
284	0.016
286	0.016
290	0.128
योग . .	<u>0.160</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत गहनौआ माइनर नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2821-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—मैला कोठार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.216 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
नम्बर	(हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136	0.152
143	0.050
757, 758, 759	0.014
योग . .	<u>0.216</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2823-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—पड़ी पवाई	(1)	(2)	(3)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.211 हेक्टेयर.			
खसरा अर्जित रकबा	153	0.053	—
नम्बर (हेक्टेयर में)	156	0.042	—
(1) (2)	158	0.049	—
311 0.023	170	0.049	—
491 0.005	168	0.061	—
553 0.017	171	0.052	—
680 0.002	167	0.028	—
682 0.010	163	0.105	—
925 0.006	160	0.045	—
2181 0.022	140	0.032	—
2212 0.096			
1374/1 0.030	139	0.069	—
योग . . <u>0.211</u>			
	137	0.113	—
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिरमौर वितरक नहर के मैला कोठार माइनर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	114	0.016	—
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	115	0.320	—
	116	0.016	—
	123	0.077	—
	122	0.053	—
	121	0.089	—
	276	0.121	—
	277	0.174	—
	266	0.012	—
	योग : <u>1.738</u>		

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2839-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—दुबगवां
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.738 हेक्टेयर.

### खसरा क्रमांक

### अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)
151	0.073	—
152	0.089	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2841-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—मङ्गियार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.614 हेक्टेयर.

### खसरा क्रमांक

### अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)
8	0.101	—
20	0.024	—
25	0.303	—
26	0.081	—
27	0.053	—
17	0.081	—
18	0.020	—
511	0.008	—
87	0.053	—
88	0.073	—
89	0.146	—
90	0.004	—
101	0.077	—
102	0.045	—
515	0.036	—
103	0.049	—
182	0.012	—
181	0.032	—
184	0.262	—
193	0.154	—
योग :	<u>1.614</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2843-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—सिरमौर
- (ग) ग्राम—कटकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—4.157 हेक्टेयर.

### खसरा क्रमांक

### अर्जित रकबा

अशासकीय भूमि (हेक्टर में)	शासकीय भूमि (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)
123	0136	—
128	0.084	—
130	0060	—
131	0.052	—
134	0.440	—
133	0.108	—
140	0.130	—
154	0.136	—
165	0.091	—
157	0.092	—
164	0.048	—
162	0.076	—
169	0.042	—
171	0.072	—
170	0.032	—
207	0.045	—
208	0.060	—
210	0.004	—

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
206	0.040	—	10	0.008	—
202	0.060	—	452	0.050	—
203	0.038	—	158	0.048	—
214	0.090	—	159	0.061	—
216	0.045	—	160	0.040	—
233	0.052	—	161	0.040	—
204	0.032	—	105	0.070	—
264	0.050	—	104	0.060	—
263	0.050	—	103	0.120	—
262	0.028	—	योग : <u>4.157</u>		
261	0.008	—	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।		
298	0.028	—	(3) भूमि का नवशा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।		
296	0.081	—	क्र. 2845-भू-अर्जन-कार्य-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		
292	0.158	—	अनुसूची		
290	0.009	—	(1) भूमि का वर्णन—		
314	0.144	—	(क) जिला—रीवा		
311	0.062	—	(ख) तहसील—सिरमौर		
312	0.072	—	(ग) ग्राम—मनवाही 452		
44	0.072	—	(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.107 हेक्टेयर।		
43	0.144	—	खसरा क्रमांक		
38	0.004	—	अर्जित रकमा		
40	0.096	—	अशासकीय भूमि		
41	0.058	—	(हेक्टर में)		
42	0.039	—	शासकीय भूमि		
39	0.024	—	(हेक्टर में)		
19	0.034	—	(3)		
18	0.102	—	(1)		
999	0.182	—	160		
16	0.006	—	0.069		
14	0.020	—	163		
20	0.004	—	0.121		
13	0.096	—	—		
12	0.020	—			
11	0.004	—			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
164	0.105	—	199	0.008	—
168	0.089	—	149	0.234	—
170	0.129	—	155	0.328	—
208	0.008	—	151	0.016	—
209	0.486	—	156	0.029	—
219	0.603	—	154	0.165	—
197	0.016	—	153	0.202	—
221	0.255	—	18	0.139	—
22	0.226	—	17	0.049	—
योग : <u>2.107</u>					
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.		21	0.125	—
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		6	0.138	—
			22	0.042	—
			23	0.028	—
			24	0.113	—
			19	0.008	—
			20	0.008	—
			30	0.089	—
			31	0.101	—
			32	0.073	—
			33	0.085	—
			34	0.008	—
			55	0.012	—
			44	0.089	—
			42	0.081	—
(1)	भूमि का वर्णन—		66	0.240	—
(क)	जिला—रीवा		63	0.010	—
(ख)	तहसील—सिरपौर		58	0.270	—
(ग)	ग्राम—पैपखरा		59	0.010	—
(घ)	लगभग क्षेत्रफल—3.579 हेक्टेयर.		60	0.125	—
खसरा क्रमांक	अर्जित रकमा		61	0.125	—
	अशासकीय भूमि	शासकीय भूमि	83	0.129	—
	(हेक्टर में)	(हेक्टर में)	89	0.239	—
(1)	(2)	(3)	87	0.016	—
201	0.113	—	88	0.239	—
203	0.012	—			
198	0.061	—			
			योग : <u>3.759</u>		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली कटकी उपशाखा नहर का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2849-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—सिरमौर  
 (ग) ग्राम—पटेहरा  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.165 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

76/987/2	0.085
583/2	0.080
योग . .	<u>0.165</u>

(ब) शासकीय भूमि	निरंक
महायोग . .	<u>0.165</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2851-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—सिरमौर  
 (ग) ग्राम—बगड़ा 337  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.125 हेक्टेयर.

खसरा	अर्जित रकबा
क्रमांक	(हे. में)
(1)	(2)

#### (अ) निजी पट्टे की भूमि

88/2	0.125
योग . .	<u>0.125</u>

(ब) शासकीय भूमि	निरंक
महायोग . .	<u>0.125</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत कटकी सिंचाई योजना के नहर निर्माण में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

(1)

(2)

एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

1531

0.10

राजस्व विभाग

1414

0.10

झाबुआ, दिनांक 18 सितम्बर 2012

1373

0.03

1386

0.01

क्र.2924-रीडर-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को

1532

0.12

इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

1699

0.02

1710

0.06

1702

0.08

1375

0.04

1374

0.06

1445

0.07

1438

0.07

1397

0.02

(1) भूमि का वर्णन—

1372

0.04

(क) जिला—झाबुआ

1395

0.02

(ख) तहसील—रानापुर

1645

0.02

(ग) ग्राम—कांकरादरा

1446

0.04

(घ) तालाब —भामची तालाब (नहर कार्य)

योग . . 1.60

सर्वे नम्बर

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

1627

0.10

1637

0.05

1707

0.06

1694

0.04

1691

0.07

1698

0.05

1638

0.04

1639

0.01

1643

0.05

1644

0.02

1559

0.03

1551

0.02

1563

0.04

1565

0.04

1543

0.05

1529

0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— भामची तालाब नहर निर्माण में आने से ग्राम कांकरादरा का कुल रकबा निजी भूमि 1.60 हेक्टर।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ/रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र.2926-रीडर-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—झाबुआ

(ख) तहसील—रानापुर

(ग) ग्राम—सुरडिया		(1)	(2)	
(घ) तालाब—भामची तालाब (नहर कार्य)		355	0.03	
सर्वे नम्बर	रकबा	474	0.07	
	(हे. में)	475	0.10	
(1)	(2)	476	0.06	
		190	0.02	
338	0.03		योग . 2.28	
337	0.04			
339	0.01	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— भामची तालाब के नहर निर्माण में आने से ग्राम सुरडिया का कुल रकबा निजी भूमि 2.28 हेक्टर.		
352	0.07			
354	0.06	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, झाबुआ/रानापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.		
444	0.01			
446	0.06	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		
497	0.05	जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		
496	0.02			
495	0.03	कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं		
490	0.06	पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		
488	0.05			
473	0.04	रायसेन, दिनांक 18 सितम्बर 2012		
29	0.06			
30	0.09	प्र. क्र. 01-अ-82--2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		
13	0.13			
33	0.06	अनुसूची		
149	0.10			
10	0.15	(1) भूमि का वर्णन—		
153	0.11	(क) जिला—रायसेन		
407	0.04	(ख) तहसील/तालुका—बेगमगंज		
411	0.13	(ग) नगर/ग्राम—इटैया, भैसबाई खुर्द, सुनेहरा		
412	0.02	(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.730 हेक्टर.		
413	0.02			
414	0.08			
432	0.02			
435	0.02			
437	0.02			
447	0.01			
434	0.02			
193	0.04			
192	0.05	खसरा	कुल रकबा	अर्जित किये जाने
194	0.04	नम्बर	(हे. में)	वाला रकबा
195	0.15			(हे. में)
196	0.01	(1)	(2)	(3)
328	0.02			
330	0.03			
336	0.02	ग्राम—इटैया		
335	0.03	42,43,44,45,46,47, 48,49/2	2.807	0.150
		39,40,41/1	1.214	0.420

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
38/1	0.081	0.030	73	3.634	0.360
39,40,41/2	1.214	0.250	74	0.308	0.020
37/2	0.121	0.050	67/1	2.377	0.040
38/2	0.081	0.020	161	2.274	0.300
39,40,41/3/1	2.108	0.080	142/2	1.040	0.230
20	2.630	0.240	142/1	1.044	0.110
29/1	1.129	0.220	263/93/2	1.230	0.240
30/1	0.506	0.090	170/1	0.619	0.080
18/1/1	1.109	0.150	171/1	1.489	0.270
18/1/2	1.214	0.120	175	1.643	0.080
42,43,44,45,46	2.803	0.150	162	2.189	0.220
47,48,49/1			96	0.243	0.020
168/83	1.012	0.170	263/93/1	0.986	0.230
83/84	2.035	0.050	93/2	3.144	0.130
85/1	1.153	0.280	93/1	0.433	0.020
88	0.146	0.010	95	1.809	0.020
89	0.619	0.170			
113	3.666	0.360			ग्राम—सुनेहरा
114	0.777	0.060			
178/114	1.942	0.050	692	1.598	0.120
115/1	0.389	0.020	693	1.531	0.120
116/1	1.148	0.260	691/1	0.603	0.070
111	3.298	0.060	699/3	0.930	0.070
116/2/1	1.019	0.120	699/2/2	0.466	0.100
116/2/2	1.506	0.080	699/1	0.929	0.100
117	1.003	0.030	702	1.404	0.240
118/2	1.214	0.050	707/1	1.214	0.030
123/2/1/1	0.425	0.080	706	2.016	0.180
123/1/1	1.306	0.100	718	2.068	0.180
123/2/2/1	0.242	0.130			कुल योग . .
					<u>8.730</u>

**ग्राम—भैसबाईखुर्द**

54/2	0.809	0.110
64/1	1.120	0.020
56	2.727	0.170
67/2	1.214	0.120
65	3.545	0.300
66	1.226	0.300
53/2	0.405	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—कीरतपुर जलाशय हेतु नहर निर्माण हेतु

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,  
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 सितम्बर 2012

क्र. 2855-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—तितरा बाघेलान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.540 हेक्टर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
14	0.58	0.157
15	0.44	0.100
17	0.53	0.090
18	0.91	0.098
19	0.41	0.030
20	0.26	0.065
	योग . .	<u>0.540</u>

गोशवारा

निजी भूमि	—	<u>0.540</u>
-----------	---	--------------

शासकीय भूमि	—	.....
-------------	---	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा बाघेलान सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.	170/1, 170/2 180 181 188 160	0.015 0.120 0.07 0.102 0.008
--	--	--

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	101	0.010
	योग . .	<u>0.1365</u>

क्र. 2857-प्रका.—भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—तितरा शुक्लान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.395 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)
80		0.120
81		0.060
82		0.060
83		0.038
84		0.054
85		0.012
86/1, 86/2		0.070
92		0.010
93		0.042
100		0.030
102		0.050
113		0.025
114		0.066
161/1, 161/2		0.054
163		0.140
164		0.044
165/1, 165/2		0.048
166		0.006
167/1, 167/2		0.174
170/1, 170/2		0.015
180		0.120
181		0.07
188		0.102
160		0.008
101	0.010	
योग . .	<u>0.1365</u>	

मध्यप्रदेश शासन की भूमि		(1)	(2)	(3)
खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	292	0.045	
119	0.018	292	0.045	
186	0.012	293	0.085	
योग . .	<u>0.030</u>	298/1	0.039	—म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग
		299/1	0.056	—म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग
		299/2		—म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग
		298/2		—म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग
		योग . .	<u>0.315</u>	
गोशवारा				
विवरण	कृषक सं.	खसरा नं.	कुल अर्जित रकबा (हे. मे.)	गोशवारा
निजी भूमि	28	30 किता	1.365	निजी भूमि 8 किता — 0.315
म. प्र. शासन की भूमि	—	2 किता	0.030	अशासकीय भूमि —
		32 किता		
		योग . .	<u>1.395</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 1 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2859-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—कोरिगर्वा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.315 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे.में)	रिमार्क (हे.में)	(1)	(2)	(3)
(1)	(2)	(3)	213	0.007	
289	0.045		214	0.010	
291	0.045		218/1		
			218/2	0.030	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2861-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—तितरा शुक्लान
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —2.113 हेक्टर।

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे.में)	रिमार्क (हे.में)	(1)	(2)	(3)
			213	0.007	

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
219/1	0.030		888	0.040	
219/2			889	0.050	
220	0.060		893/1/1		
221	0.016		893/1/2		0.090
268/1	0.020		893/1/3		
269/1	0.075		894/1/4		
289	0.071		893/2		
290	0.020		904	0.015	
291	0.025		905	0.015	
292	0.038		906	0.030	
293/1			907	0.045	
293/2			909	0.055	
293/3/1	0.090		911	0.055	
294/3/2			912/1		0.025
294	0.030		912/2		
296	0.060		913	0.012	
555	0.015		914	0.015	
558	0.010		915	0.020	
559	0.060		916	0.006	
560	0.090		917	0.036	
579/1	0.112		योग :		<u>2.095</u>
579/2					
580	0.075				
581/1	0.025		434	0.018	
581/2			योग :		<u>0.018</u>
583	0.040				
584	0.075				
585	0.021		निजी भूमि 65 किता	2.095	
586	0.015		शासकीय भूमि	0.018	
588	0.030		महा योग :		<u>2.113</u>
837/1	0.075				
837/2			(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 2 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.		
838	0.060				
849	0.070		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.		
850	0.075				
851	0.030				
875	0.040				
876	0.020		क्र. 2863—प्रका.—भू—अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू—अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धांरा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित		
877	0.020				
878	0.020				
879	0.018				
880	0.015				

संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
- (ग) ग्राम—तितरा शुक्लान
- (घ) क्षेत्रफल—1.260 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा  
(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
645/1	0.028
646/1	
646/2	0.028
650/1	
650/2/1	
650/2/2	0.030
650/2/3	
653	0.045
654	0.005
655	0.050
663	0.095
666	0.175
993	0.100
994	0.155
1002	0.006
1003	0.015
1013/1	0.040
1013/2	
1014	0.040
1016	0.070
1017	0.055
1019	0.090
1020	0.012
1021	0.075
1022	0.040
1023	0.070
650/1029/1	0.015
650/1029/2	
योग :	1.239

**म. प्र. शासन की भूमि**

1000	0.015
1001	0.006
योग :	0.021

**गोशवारा**

निजी भूमि 26 किता	1.239
म. प्र. शासन की भूमि 2 किता	0.021

**महायोग :** 1.260

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत तितरा सब माइनर क्र. 3 में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्र. 2891-प्रका.-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

**अनुसूची**

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगढ़ां
- (ग) ग्राम—आलमगंज 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.065 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
678/378	0.065
योग :	<u>0.065</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के आलमगंज चितरिका नहर माइनर नं. 3 के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2893-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवाँ
- (ग) ग्राम—कठेरी पबाई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.124 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
251	0.124
योग :	0.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर के धैवता वितरक नहर की कठेरी माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2896-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—लौलाछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.502 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
192	0.192	—
670	0.248	—
234	0.024	—
187	0.038	—
योग :		0.502

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2898-भू-अर्जन-कार्य-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
- (ख) तहसील—कोटर
- (ग) नगर/ग्राम—पिपराछा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.124 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
80	0.124	—

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत पुरवा नहर के वितरण मुख्य नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परि., रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2012

क्र. 2909-भू-अर्जन--20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा  
 (ख) तहसील—गुढ़  
 (ग) नगर/ग्राम—लखड़ी  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.009 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
182/1	0.009
योग :	<u>0.009</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की कनौजा माइनर नं. 2 की सब-माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शास. भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर परि., रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 बी. बी. श्रीवांस्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 21 सितम्बर 2012

प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12-म्याना-616.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—गुना  
 (ख) तहसील—गुना  
 (ग) नगर/ग्राम—म्याना  
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—11.234 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1001/1 में से	0.565
1002 में से	0.700
1003/2/2 में से	0.105
1003/2/3 में से	0.169
1003/2/4 में से	0.399
1003/3	1.000
1003/4 में से	1.186
1003/5 में से	1.082
1003/6 में से	1.686
1003/7 में से	0.658
1005/1 ख	0.554
1005/2 में से	0.126
1005/3 में से	1.523
1006 में से	0.169

(1)	(2)	(1)	(2)
1030 में से	0.021	2/5/2 में से	0.847
1032/1 में से	0.523	2/5/3 में से	0.209
1032/8 में से	0.512	2/6 में से	0.268
1032/9 में से	0.256	2/7/1 में से	0.345
योग . .	<u>11.234</u>	2/7/2 में से	1.285
		2/7/3 में से	1.129

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीछई लघु सिंचाई परियोजना (बांध+दूबक्षेत्र).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 15-अ-82-2011-12-रीछई-617.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—गुना
- (ख) तहसील—गुना
- (ग) नगर/ग्राम—रीछई
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—8.199 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/2 में से	0.073
2/3/2 में से	0.198
2/4 में से	1.233
2/5/1 में से	0.376

2/8 में से	0.178
2/10 में से	0.325
59/1 में से	0.126
59/2 में से	0.361
59/3 में से	0.116
61 में से	0.073
62 में से	0.064
75/1 में से	0.105
76 में से	0.094
77 में से	0.199
81 में से	0.052
82 में से	0.010
83/1 में से	0.051
84 में से	0.398
89/2/1 में से	0.084
योग . .	<u>8.199</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—रीछई लघु सिंचाई परियोजना (बांध+दूबक्षेत्र).

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, गुना के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश) — 462011

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2012

#### आदेश

क्र. एफ. 67-111-10-तीन-1643.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके परिणाम की घोषणा की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या यह उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अधिकार्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) अदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा के आम निर्वाचन में सुश्री रिति सिंह, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा के पत्र क्र. 565-स्था.नि.-10, दिनांक 20 अप्रैल 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रिति सिंह द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रिति सिंह को कारण बताओ नोटिस दिनांक 5 मई 2010 जारी किया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर

कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 7 अगस्त 2010 के माध्यम से संशोधित परिशिष्ट छत्तीस आयोग को प्रेषित किया, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा लेखे दिनांक 2 जुलाई 2010 को प्रस्तुत किये जाने का लेख करते हुए अंकित किया कि “अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा में कोई राशि व्यय करना नहीं दर्शाया है, परन्तु प्रतिभूति राशि भी व्यय की श्रेणी में आती है। वह भी नहीं दर्शाई गई है।” अतः आयोग के पत्र दिनांक 20 अगस्त 2010 के द्वारा कलेक्टर, विदिशा को निर्देशित किया गया कि अभ्यर्थी को जिलास्तर से नोटिस जारी कर अपूर्ण लेखों को पूर्ण करवाए जाने हेतु नोटिस जारी किया जावे। इसके साथ ही अभ्यर्थी द्वारा यदि विलम्ब से लेखे प्रस्तुत करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है तो अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों की स्वीकार्यता/अस्वीकार्यत के संबंध में अभिमत चाहा गया।

सुश्री रिति सिंह को नोटिस दिनांक 25 मई 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 9 जून 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत उप जिला निर्वाचन अधिकारी, विदिशा ने अपने पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2012 में लेख किया कि सुश्री रिति सिंह द्वारा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आयोग द्वारा दिनांक 15 जून 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 30 जुलाई 2012 को उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से प्रेषित किया गया, किन्तु अभ्यर्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रिति सिंह को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद विदिशा, जिला विदिशा का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(ए. के. शर्मा )

प्रभारी सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।